



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 555] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 31, 2018/पौष 10, 1940  
No. 555] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 31, 2018/PAUSHA 10, 1940

## भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

### अधिसूचना

मुम्बई, 31 दिसम्बर, 2018

## भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

### (विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता निवेशक) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/58.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (खक) तथा धारा 12 की उप-धारा (1) एवं (1क) के साथ पठित धारा 30 की उप-धारा (1) और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] विनियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,—

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त (लागू) होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] विनियम, 2014 में,—  
क. विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में,—

- i. खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

“(गक) “नियंत्रण” में शामिल है - बहुसंख्या में निदेशकों (डायरेक्टर्स) को नियुक्त करने का अथवा प्रबंध-मंडल (प्रबंधन / मैनेजमेंट) या नीतिगत निर्णयों (विनिश्चयों) को नियंत्रित करने का अधिकार, जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति द्वारा अथवा अलग-अलग या सामान्य मति से कार्य करने वाले व्यक्तियों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, किया जा सकता है, जिसमें वह अधिकार भी शामिल है जो

शेयरधारिता (शेयरहोल्डिंग) या प्रबंधन संबंधी अधिकारों अथवा शेयरधारक करारों (एग्रीमेंट) या मतदान करारों की वजह से या किसी अन्य प्रकार से मिलता हो;”

ii. खंड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

“(झक) “निवेश प्रबंधक (इन्वेस्टमेंट मैनेजर)” से निवेश प्रबंधन (इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट), निवेश सलाहकार (इन्वेस्टमेंट एडवाइज़री) की भूमिका या ऐसी ही कोई अन्य भूमिका निभाने वाली एंटीटी [जिसमें न्यासी (ट्रस्टीज़) शामिल हैं] अभिप्रेत है;”

ख. विनियम 4 में, -

i. उप-विनियम (1) में, खंड (ड) के पश्चात्, निम्नलिखित नए खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्, -

“(डक) जहाँ अनिवासी भारतीय या भारत का विदेशी नागरिक या निवासी भारतीय आवेदक या मौजूदा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक का घटक हो, वहाँ-

(i) किसी एक अनिवासी भारतीय या भारत के विदेशी नागरिक या निवासी भारतीय की हिस्सेदारी आवेदक या मौजूदा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के कॉर्पस की कुल हिस्सेदारी के पच्चीस प्रतिशत से कम होगी;

(ii) अनिवासी भारतीयों, भारत के विदेशी नागरिकों और निवासी भारतीयों की कुल हिस्सेदारी आवेदक या मौजूदा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के कॉर्पस में कुल हिस्सेदारी के पचास प्रतिशत से कम होगी;

स्पष्टीकरण: वैश्विक निधियों (ग्लोबल फंड्स) [जिनका भारतीय एक्सपोज़र 50% से कम हो] में निवासी भारतीय की हिस्सेदारी की अनुमति है यदि वह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मंजूर की गई उदारीकृत विप्रेषण योजना (लिब्रलाइज़्ड रेमिटेंस स्कीम / एलआरएस) के जरिए की जाए।

(iii) अनिवासी भारतीयों, भारत के विदेशी नागरिकों और निवासी भारतीयों के पास आवेदक का या मौजूदा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक का नियंत्रण नहीं होगा:

उप-खंड (iii) में दी हुई कोई भी बात लागू नहीं होगी, यदि आवेदक या मौजूदा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक ऐसी ‘अपतटीय निधि (ऑफशोर फंड)’ हो, जिसके लिए बोर्ड द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 [सेबी (म्यूचुअल फंड्स) रेग्यूलेशन्स, 1996] के अनुसार ‘अनापत्ति प्रमाणपत्र’ जारी किया गया हो, या जो ऐसे निवेश प्रबंधक (इन्वेस्टमेंट मैनेजर) द्वारा नियंत्रित हो जो अनिवासी भारतीय या भारत के विदेशी नागरिक या निवासी भारतीय के नियंत्रणाधीन और/या स्वामित्वाधीन हो, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाएँ:

I. ऐसा निवेश प्रबंधक (इन्वेस्टमेंट मैनेजर) उसके अपने देश में समुचित रूप से विनियमित हो और निवेश न करने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के रूप में बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत हो, या

II. ऐसे निवेश प्रबंधक का निगमन या गठन भारत के कानूनी प्रावधानों के तहत हुआ हो और वह समुचित रूप से बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत हो।

खंड (डक) में दी हुई कोई भी बात निवेश न करने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक पर लागू नहीं होगी अथवा यदि आवेदक या मौजूदा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक केवल भारत में पारस्परिक निधियों (म्यूचुअल फंड्स) द्वारा चलाई जा रही स्कीमों की यूनिटों में निवेश करने का प्रस्ताव करता हो या निवेश करता हो, तो भी लागू नहीं होगी।

(डख) आवेदक और मौजूदा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक तथा उनके वे अंडरलाइंग निवेशक जिनकी आवेदक या मौजूदा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के कॉर्पस में पच्चीस प्रतिशत या उससे अधिक की हिस्सेदारी हो अथवा नियंत्रण के आधार पर जिनकी पहचान ऐसे व्यक्तियों के रूप में हो जिनके नाम का उल्लेख संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूनाइटेड नेशन्स सिक्यूरिटी काउंसिल) द्वारा समय-समय पर

अधिसूचित की जाने वाली अनुशास्तियों संबंधी सूची (सैंक्शन्स लिस्ट) में न हो और जो ऐसे देश से न हों जिसकी पहचान वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स) की सार्वजनिक घोषणा में:

- (i) ऐसे देश के रूप में हो, जिसकी धन-शोधन निवारण से संबंधित नीतियों में खामियाँ हों या जो आतंकवाद का वित्तपोषण करने संबंधी स्थितियों से जूझ रहा हो और जिसे इनके खिलाफ कदम उठाने हों; या
  - (ii) ऐसे देश के रूप में हो, जिसने खामियों को दूर करने के लिए पर्याप्त कदम न उठाए हों या जो खामियों को दूर करने के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स) के साथ मिलकर बनाई गई कार्य-योजना (एक्शन प्लान) के प्रति प्रतिबद्ध न हो।”
- ii. मौजूदा उप-विनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-
- “(2)(1) आवेदक या मौजूदा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, इस विनियम के प्रवृत्त (लागू) होने की तारीख से या रजिस्ट्रीकरण की तारीख से (जो भी बाद में हो), दो वर्षों की अवधि के भीतर, उप-विनियम (1) के खंड (डक) का पालन करेगा।
- (2) मौजूदा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, इस विनियम के प्रवृत्त (लागू) होने की तारीख से तीन महीनों की अवधि के भीतर, उप-विनियम (1) के खंड (डख) का पालन करेगा।
- (3) जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक इस उप-विनियम के खंड (1) एवं (2) में निर्धारित की गई अवधि के बाद भी पालन नहीं करता, उसे प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) की कोई नई खरीद करने से प्रतिषिद्ध कर दिया जाएगा, और ऐसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भारत के प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में अपनी मौजूदा पोजीशन को, एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के भीतर, बेचेगा।
- (4) यदि उप-विनियम (1) के खंड (डक) में निर्धारित की गई निवेश संबंधी सीमाओं का अस्थायी उल्लंघन हो जाता है, तो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक इस प्रकार उल्लंघन होने के नब्बे दिनों के भीतर पात्रता संबंधी शर्तों का पालन करेगा और यदि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक नब्बे दिनों के बाद भी उपरोक्त अपेक्षा का पालन न करता हो, तो किसी भी नई खरीद की अनुमति नहीं होगी, और ऐसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भारत के प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में अपनी मौजूदा पोजीशन को, अगले एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के भीतर, बेचेगा।”
- iii. स्पष्टीकरण में, खंड (i), (ii) एवं (iii) निम्नलिखित खंडों से प्रतिस्थापित हो जाएंगे, अर्थात्, -
- “(i) शब्द “व्यक्ति” का वही अर्थ होगा जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 [फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, 1999] के तहत इसके लिए नियत है;
- (ii) शब्दों “अनिवासी भारतीय” और शब्द “भारत का विदेशी नागरिक” का वही अर्थ होगा जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 [फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, 1999] के तहत बनाए गए विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2017 [फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट (ट्रांसफर ऑर इश्यू ऑफ सिक्यूरिटी बाय ए पर्सन रेसीडेन्ट आउटसाइड इंडिया) रेग्यूलेशन, 2017 के विनियम 2 में इन शब्दों के लिए नियत है;
- (iii) शब्दों “भारत में निवासी” का वही अर्थ होगा जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 [फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, 1999] के तहत शब्दों “भारत में निवासी व्यक्ति” के लिए नियत है।

ग. विनियम 5 में,

- i. आरंभ में दिए हुए चिह्नों और अंक “(1)” का लोप हो जाएगा।
- ii. खंड (क) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"स्पष्टीकरण: "सरकारी एजेंसी" से वह एंटिटी अभिप्रेत होगी, जिसमें स्वामित्व या नियंत्रण का 75% से अधिक किसी दूसरे देश की सरकार द्वारा धारित हो।"

घ. विनियम 21 में, उप-विनियम (6) में, शब्द "के प्रयोजनार्थ", शब्द, अंक और चिह्न "की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (क) में यथा परिभाषित" से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

ङ. विनियम 22 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ग) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"(ग) ऐसे अपतटीय व्युत्पत्ती लिखत (ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रुमेंट्स) उन व्यक्तियों को निर्गमित (इश्यू) या अंतरित (ट्रांसफर) नहीं किए जाएंगे, जो विनियम 4 में निर्धारित शर्तों को पूरा न करते हों।"

च. विनियम 23 में, -

i. उप-विनियम (1) में, खंड (ग) में, शब्द "में कोई तात्विक", चिह्नों और शब्दों "(जिसमें उसकी संरचना या स्वामित्व या नियंत्रण में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हुए किसी परिवर्तन से संबंधित जानकारी शामिल है) में कोई महत्वपूर्ण (तात्विक)" से प्रस्थापित हो जाएंगे।

ii. मौजूदा उप-विनियम (3) निम्नलिखित उप-विनियमों से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

(3) पचास प्रतिशत से अधिक समान स्वामित्व (कॉमन ओनरशिप) [फिर चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से] वाली या समान नियंत्रण वाली विभिन्न एंटिटियों को एक ही निवेशक समूह का हिस्सा माना जाएगा और ऐसी सभी एंटिटियों की निवेश सीमाओं को एकसाथ मिला दिया जाएगा तथा उन पर वही निवेश सीमा लागू होगी जो किसी एक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के लिए लागू है।

(3क) उप-विनियम (3) में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, समान नियंत्रण वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की निवेश सीमा को उन मामलों में एकसाथ नहीं मिलाया जाएगा, जहाँ:

- (i) विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक समुचित रूप से विनियमित पब्लिक रिटेल फंड हों; या
- (ii) विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक ऐसे पब्लिक रिटेल फंड हों, जिनका अधिकांश स्वामित्व समुचित रूप से विनियमित पब्लिक रिटेल फंड के पास लूक थ्रू आधार पर हो; या
- (iii) विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक पब्लिक रिटेल फंड हों और ऐसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के निवेश प्रबंधक समुचित रूप से विनियमित हों।

स्पष्टीकरण - पब्लिक रिटेल फंड से अभिप्रेत है -

- (i) पारस्परिक निधियाँ (म्यूचुअल फंड्स) या यूनिट ट्रस्ट जिनमें छोटे निवेशक पैसे लगा (अभिदान / सब्सक्रिप्शन कर) सकते हों और जिनमें किसी विशेष निवेशक (जैसे अक्रेडिटिड निवेशक) जैसी अपेक्षाएँ नहीं होती;
- (ii) बीमा कंपनियाँ जहाँ एक-एक निवेशक का अलग-अलग पोर्टफोलियो नहीं रखा जाता;
- (iii) "पेंशन निधियाँ।"

iii. नए अंतःस्थापित उप-विनियम (3क) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-विनियम, उप-विनियम (4) के रूप में अंतःस्थापित और संख्यांकित किया जाएगा, अर्थात्,-

"(4) जहाँ ऐसी पब्लिक रिटेल निधियों के लिए समान स्वामित्व या नियंत्रण की पहचान की जाती हो, वहाँ निवेश के संकेंद्रण (इनवेस्टमेंट कंसन्ट्रेशन) पर समुचित रूप से नज़र (मॉनीटर करने) रखने हेतु, भारतीय निक्षेपागार (डिपॉज़िटरी) नाम, पते, राष्ट्रीयता, पासपोर्ट संख्या / सरकार द्वारा जारी किए गए किसी अन्य पहचान कार्ड के आधार पर नियंत्रण रखने वाली एंटिटियों के विवरण रखेंगे और समय-समय पर बोर्ड को समुचित रिपोर्टें प्रस्तुत करेंगे।"

- iv. मौजूदा उप-विनियम (4) उप-विनियम (5) के रूप में पुनःसंख्यांकित हो जाएगा और शब्द "हिताधिकारी स्वामित्व", शब्दों "संयुक्त स्वामित्व या नियंत्रण" से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

छ. विनियम 32 में,-

- i. उप-विनियम (1) में, खंड (च) में, स्पष्टीकरण 1 और 2 निम्नलिखित स्पष्टीकरणों से प्रतिस्थापित हो जाएंगे, अर्थात्,-

**"स्पष्टीकरण 1.** - इस खंड के प्रयोजनार्थ, "अपारदर्शी संरचना" से कोई संरचना, जैसे (i) प्रोटेक्टिड सैल कंपनी, सेगरिगेटेड सैल कंपनी या समतुल्य, अभिप्रेत होगी, जहाँ अंतिम हिताधिकारी स्वामियों के ब्यौरे पहुँचयोग्य न हों या जहाँ हिताधिकारी स्वामी एक दूसरे से अलग-अलग हों या जहाँ हिताधिकारी स्वामी (बेनिफिशियल ओनर) प्रवर्तन के संबंध में एक दूसरे से अलग-अलग हों, या (ii) जहाँ आवेदक या उसके निवेशक (निवेशकों) की पहचान हिताधिकारी स्वामी की पहचान हेतु निर्धारित सीमा-रेखा (श्रेसहोल्ड) के आधार पर की गई हो और उसने (उन्होंने) कोई धारक शेयर (बेयर शेयर) जारी किए हों या पहले से जारी किए गए कोई धारक शेयर रखे हुए हों:

परंतु यह कि निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक को अपारदर्शी संरचना वाला नहीं माना जाएगा :

- (i) आवेदक उसके अपने देश में विनियमित हो;
- (ii) आवेदक की प्रत्येक निधि (फंड) या उप-निधि (सब-फंड) व्यापक (विस्तृत) आधारीय मानदंडों को पूरा करती हो;
- (iii) आवेदक अपने हिताधिकारी स्वामियों (बेनिफिशियल ओनर) के संबंध में जानकारी, जब कभी बोर्ड यह जानकारी मांगे, प्रदान करने का वचन देता हो; और
- (iv) आवेदन यह वचन प्रस्तुत करे कि उसके पास पहले से जारी किए गए कोई धारक शेयर (बेयर शेयर) नहीं हैं और वह भविष्य में धारक शेयर (बेयर शेयर) जारी नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण 2. - शब्दों "अंतिम हिताधिकारी स्वामी" का वही अर्थ होगा जो धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (एंटी मनी लॉण्ड्रिंग एक्ट, 2002) के तहत यथा परिभाषित शब्दों "हिताधिकारी स्वामी" के लिए नियत है।"

- ii. उप-विनियम (2) में, खंड (च) में, शब्द "हिताधिकारी स्वामित्व", शब्दों "समान स्वामित्व या नियंत्रण" से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

ज. दूसरी अनुसूची में, भाग क में, खंड (4) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -

"(4) जहाँ एक से अधिक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (विनिधानकर्ताओं) का प्रत्यक्ष रूप से / अप्रत्यक्ष रूप से समान स्वामित्व या नियंत्रण हो, वहाँ केवल एक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (विनिधानकर्ता) को प्रवर्ग I के तहत रजिस्ट्रीकरण फीस के भुगतान से छूट होगी और अन्य विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (विनिधानकर्ता) प्रवर्ग II के लिए यथा लागू रजिस्ट्रीकरण फीस अदा करेंगे, उन मामलों को छोड़कर जहाँ समान स्वामित्व या नियंत्रण विश्व बैंक (वर्ल्ड बैंक) और अन्य संस्थाओं जैसी एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय/बहुपक्षीय एजेंसी का हो, जो सहायता प्रदान करने के लिए भारत के बाहर स्थापित है और जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेषाधिकार प्रदान किए गए हों तथा कर एवं शुल्कों के भुगतान से छूट (उन्मुक्तियाँ) प्रदान की गई हो।"

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./474/18]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/36/12 द्वारा, 7 जनवरी 2014 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] विनियम, 2014 तत्पश्चात् :
- (क) 8 जुलाई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] (संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/009, द्वारा
- (ख) 12 जनवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/018, द्वारा
- (ग) 27 फरवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/035, द्वारा
- (घ) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037 (तारीख 29 मार्च, 2017 की अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/038 के साथ पठित), द्वारा
- (ङ) 29 मई, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/004, द्वारा
- (च) 20 जुलाई, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] (चौथा संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/012, द्वारा
- (छ) 5 अप्रैल, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] (संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/05, द्वारा
- (ज) 27 अप्रैल, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/08, द्वारा संशोधित हुए थे।

## SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA NOTIFICATION

Mumbai, the 31st December, 2018

### Securities And Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Third Amendment) Regulations, 2018

**No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/58.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 30 read with sub-section (1) of section 11, clause (ba) of sub-section (2) of section 11 and sub-sections (1) and (1A) of section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and section 25 of the Depositories Act, 1996, the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2014, namely,—

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Third Amendment) Regulations, 2018.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2014, -
  - a. in regulation 2, in sub-regulation (1), -
    - i. after clause (c), the following new clause shall be inserted, namely, -

“(ca) “control” includes the right to appoint majority of the directors or to control the management or policy decisions exercisable by a person or persons acting individually or in concert, directly or indirectly, including by virtue of shareholding or management rights or shareholders agreements or voting agreements or in any other manner;”

ii. after clause (i), the following new clause shall be inserted, namely, -

“(ia) “Investment Manager” means an entity performing the role of investment management, investment advisory or any equivalent role, including trustees;”

b. in regulation 4, -

i. after clause (e), the following new clauses shall be inserted, namely, -

“(ea) where non-resident Indians or overseas citizens of India or resident Indians are constituents of the applicant or an existing foreign portfolio investor -

(i) the contribution of a single non-resident Indian or overseas citizen of India or resident Indian shall be below twenty-five percent. of the total contribution in the corpus of the applicant or the existing foreign portfolio investor;

(ii) the aggregate contribution of non-resident Indians, overseas citizens of India and resident Indians shall be below fifty percent. of the total contribution in the corpus of the applicant or the existing foreign portfolio investor;

Explanation: The contribution of Resident Indian is permitted if made through the Liberalised Remittance Scheme (LRS) approved by Reserve Bank of India in global funds whose Indian exposure is less than 50%.

(iii) the non-resident Indians, overseas citizens of India and resident Indians shall not be in control of the applicant or of the existing foreign portfolio investor:

Nothing contained in sub-clause (iii) shall apply if the applicant or an existing foreign portfolio investor is an ‘offshore fund’ for which ‘No Objection Certificate’ has been issued by the Board in terms of the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, or is controlled by an Investment Manager which is controlled and/or owned by non-resident Indian or overseas citizen of India or resident Indian if the following conditions are satisfied:

I. such Investment Manager is appropriately regulated in its home jurisdiction and registered with the Board as a non-investing foreign portfolio investor, or

II. such Investment Manager is incorporated or setup under the Indian laws and appropriately registered with the Board.

Nothing contained in clause (ea) shall apply to non-investing foreign portfolio investor or if the applicant or an existing foreign portfolio investor proposes to invest or invests only in units of schemes floated by mutual funds in India.

(eb) the applicant and an existing foreign portfolio investor and their underlying investors contributing twenty-five percent. or more in the corpus of the applicant or existing foreign portfolio investor or identified on the basis of control, shall not be persons mentioned in the Sanctions List notified from time to time by the United Nations Security Council and shall not be from a jurisdiction which is identified in the public statement of the Financial Action Task Force as:

(i) a jurisdiction having a strategic Anti-Money Laundering or Combating the Financing of Terrorism deficiencies to which counter measures apply; or

- (ii) a jurisdiction that has not made sufficient progress in addressing the deficiencies or has not committed to an action plan developed with the Financial Action Task Force to address the deficiencies.”
- ii. the existing regulation shall be numbered as sub-regulation (1) and after the said numbered sub-regulation, the following new sub-regulation shall be inserted, namely, -
- “(2)(1) An applicant or an existing foreign portfolio investor shall comply with clause (ea) of sub-regulation (1) within a period of two years from the date of coming into force of this regulation or from the date of registration, whichever is later.
- (2) An existing foreign portfolio investor shall comply with clause (eb) of sub-regulation (1) within a period of three months from the date of coming into force of this regulation.
- (3) A foreign portfolio investor who remains non-compliant even after the period specified in clauses (1) and (2) of this sub-regulation shall be prohibited from making any fresh purchase of securities and such foreign portfolio investor shall liquidate its existing position in the Indian securities market within a period of one hundred and eighty days.
- (4) In case of temporary breach of investment limits specified in clause (ea) of sub-regulation (1), the foreign portfolio investor shall comply with the eligibility conditions within ninety days of the breach and in case the foreign portfolio investor remains non-compliant with the said requirement even after ninety days, then no fresh purchases shall be permitted and such foreign portfolio investor shall liquidate its existing position in Indian securities market within a period of the next one hundred and eighty days.”
- iii. in the Explanation, clauses (i), (ii) and (iii) shall be substituted with the following clauses, namely, -
- “(i) The term “person” shall have the same meaning as assigned to it under the Foreign Exchange Management Act, 1999;
- (ii) The terms “non-resident Indian” and “overseas citizen of India” shall have the same meaning as assigned to such terms under regulation 2 of the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2017 made under the Foreign Exchange Management Act, 1999;
- (iii) The term “resident in India” shall have the same meaning assigned to the term “person resident in India” under the Foreign Exchange Management Act, 1999.”
- c. in regulation 5, in clause (a), the following Explanation shall be inserted, namely, -
- “Explanation: A “government agency” shall mean an entity in which more than 75% of ownership or control is held by the Government of a foreign country.”
- d. in regulation 21, in sub-regulation (6), for the words “for the purposes”, the symbol and words “, as defined in clause (a) of sub-section (1) of section 2” shall be substituted.
- e. in regulation 22, in sub-regulation (1), in clause (c), for the words “are resident Indians or non-resident Indians and to entities that are beneficially owned by resident Indians or non-resident Indians”, the words and number “do not satisfy the conditions specified in regulation 4” shall be substituted.
- f. in regulation 23, -
- i. in sub-regulation (1), in clause (c), after the word “information” and before the word “previously”, the words and symbol “including any direct or indirect change in its structure or ownership or control,” shall be inserted.



- ii. the existing sub-regulation (3) shall be substituted with the following sub-regulations, namely, -

“(3) Multiple entities having common ownership, directly or indirectly, of more than fifty percent. or common control shall be treated as being part of the same investor group and the investment limits of all such entities shall be clubbed at the investment limit as applicable to a single foreign portfolio investor.

(3A) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (3), the clubbing of investment limit of foreign portfolio investors having common control shall not be applicable where:

- (i) the foreign portfolio investors are appropriately regulated public retail funds; or
- (ii) the foreign portfolio investors are public retail funds majority owned by appropriately regulated public retail fund on look through basis; or
- (iii) foreign portfolio investors are public retail funds and Investment Managers of such foreign portfolio investors are appropriately regulated.

**Explanation -** Public retail funds means -

- (i) mutual funds or unit trusts which are open for subscription to retail investors and which do not have specific investor type requirements like accredited investors;
- (ii) insurance companies where segregated portfolio with one to one correlation with a single investor is not maintained; and
- (iii) pension funds.

- iii. after the newly inserted sub-regulation (3A), the following new sub-regulation shall be inserted and numbered as sub-regulation (4), namely, -

“(4) In order to appropriately monitor investment concentration where common ownership or control is identified for such public retail funds, the Indian depositories shall maintain details of controlling entities on the basis of name, address, nationality, passport number/ any other identification card issued by Government and provide appropriate reports to the Board on a periodic basis.”

- iv. the existing sub-regulation (4) shall be renumbered as sub-regulation (5) and the words “beneficial ownership” shall be substituted with the words “common ownership or control”.

- g. in regulation 32, -

- i. in sub-regulation (1), in clause (f), Explanations 1 and 2 shall be substituted with the following Explanations, namely, -

**“Explanation 1.** - For the purposes of this clause, "opaque structure" shall mean any structure such as (i) protected cell company, segregated cell company or equivalent, where the details of the ultimate beneficial owners are not accessible or where the beneficial owners are ring fenced from each other or where the beneficial owners are ring fenced with regard to enforcement, or (ii) where applicant or its investor(s) identified on basis of threshold for identification of beneficial owner have issued any bearer shares or maintain any outstanding bearer shares.

Provided that the foreign portfolio investor satisfying the following criteria shall not be treated as having opaque structure:

- (i) the applicant is regulated in its home jurisdiction;
- (ii) each fund or sub fund in the applicant satisfies broad based criteria;

- (iii) the applicant gives an undertaking to provide information regarding its beneficial owners as and when Board seeks this information; and
- (iv) the applicant submits an undertaking that it does not maintain any outstanding bearer shares and it would not issue bearer shares in future.

**Explanation 2.** - The phrase “ultimate beneficial owner” shall have the same meaning assigned to the term “beneficial owner” as defined under the Prevention of Money Laundering Act, 2002.”

- ii. in sub-regulation (2), in clause (f), the words “beneficial ownership” shall be substituted with the words “common ownership or control”.
- h. in the Second Schedule, in Part A, in clause (4), -
  - i. the words “common beneficial owners(s)” shall be substituted with the words “direct/indirect common ownership or control”; and
  - ii. the words “beneficial owner is” shall be substituted with the words “common ownership or control is of”.

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty.474/18]

**Footnote:**

1. The Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2014 were published in the Gazette of India on 7th January, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2013- 14/36/12.
2. The Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2014, were subsequently amended on:
  - (a) July 8, 2016 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Amendment) Regulations, 2016 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/009;
  - (b) January 12, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/018;
  - (c) February 27, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Second Amendment) Regulations, 2017 vide notification no. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/035;
  - (d) March 6, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification no. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/037 read with notification no. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/38 dated March 29, 2017;
  - (e) May 29, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Third Amendment) Regulations, 2017 vide notification no. SEBI/LAD/NRO/GN/2017-18/04.
  - (f) July 20, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Fourth Amendment) Regulations, 2017 vide notification no. SEBI/LAD/NRO/GN/2017-18/12.
  - (g) April 05, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/05.
  - (h) April 27, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Second Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/08.